वाशिंगटन की कल्पना

लेखक-मोहम्मद अयूब (प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

1 मई, 2019

"ईरानी तेल निर्यात पर अमेरिकी रुख पश्चिम एशिया में केवल तबाही का कारण बन सकता है।"

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने 22 अप्रैल को घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरानी तेल के मौजूदा आयातकों को कोई अतिरिक्त 'महत्वपूर्ण कटौती अपवाद' (SREs) जारी नहीं करेगा, जिन्हें पिछले साल नवंबर में इस तरह की छूट मिली थी। श्री पोम्पिओ ने घोषणा की कि इसका उद्देश्य ईरानी तेल निर्यात को 'शून्य' पर लाना है। भारत, चीन और तुर्की, ईरान से तेल आयात करने वाले प्रमुख देश है, जिन पर 2 मई से लागू होने वाली इस नीति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा।

इस छूट के अंत के बाद मुख्य आयातकों से अलग प्रतिक्रियाएं मिलने की उम्मीद की जा रही है। इसकी संभावना काफी है कि चीन, जो ईरानी तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, अमेरिकी फैसले की उपेक्षा करेगा क्योंकि चीन एक महान शक्ति है और वह अमेरिका को एक संभावित चुनौती के रूप में देखता है, जिसके सामने वह झुकना नहीं चाहेगा। इसके अलावा, बीजिंग एकतरफा प्रतिबंधों का दृढ़ता से विरोध कर रहा है क्योंकि इसे डर है कि एक दिन इसे भी इसी तरह के उपचार के अधीन किया जा सकता है।

तुर्की और ईरान ने कुर्द अलगाववाद, इराक की क्षेत्रीय अखंडता और सऊदी अरब के प्रति असहमति साझा करने के संबंध में रणनीतिक हितों को ओवरलैप किया है। ईरान, तुर्की को ऊर्जा प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता है और प्रमुख व्यापारिक साझेदार भी है। इसके अलावा, अमेरिका के साथ तुर्की के संबंध वर्तमान में सीरियाई कुर्द मिलिशिया, वाईपीजी (YPG, यह एक संक्षिप्त नाम है, जिसके अनुवाद का मतलब पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स है,यह सीरिया के कुर्दिश इलाके का रक्षा बल है।) के अमेरिकी समर्थन के कारण कठिन बन गये है, जिसे अंकारा आतंकवादी संगठन पीकेके के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण आतंकवादी संगठन मानता है।

रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के निर्णय के बाद तुर्की पर अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा भी दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण है। इसलिए, इसकी संभावना नहीं है कि तुर्की पूरी तरह से अमेरिकी इच्छाशक्ति के आगे झुक जाएगा, हालांकि, वह अपने नाटो सहयोगी राष्ट्रों को सांत्वना देने के लिए आंशिक रूप से ऐसा कर भी सकता है।

भारतीय आत्मसमर्पण?

जहाँ भारत के राजनेता कठिन लड़ाई वाले चुनाव प्रचार में और नीति निर्माता घरेलू परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने में वयस्त हैं, वहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका का यह फैसला भारतीय संदर्भ में इससे बुरे समय में नहीं आ सकता था। फिर भी, भारत की स्थिति चीन और तुर्की की तुलना में सबसे कमजोर है। नई दिल्ली द्वारा अमेरिकी मांगों का अनुपालन करने की संभावना अधिक इसलिए है, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका के साथ भारत के संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं।

यू.एस. भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और विदेशी निवेश का एक प्रमुख स्रोत है। यह सामरिक क्षेत्र के साथ-साथ भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन को लेकर अमेरिकी और भारतीय हितों के अभिसरण के कारण भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अलावा, अमेरिका के साथ परमाणु संबंध भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह में प्रवेश करने के लिए भारत

को अमेरिकी समर्थन की आवश्यकता है।

हालांकि, अमेरिकी फैसले का अनुपालन बिना लागत के संभव नहीं होगा। भारत दक्षिणी ईरान में चाबहार बंदरगाह के निर्माण में पूरी तरह से शामिल है। इस बंदरगाह से भारत के लिए न केवल ईरान, बल्कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक शत्रुतापूर्ण पाकिस्तानी क्षेत्र को दरकिनार करने के लिए एक प्रमुख पहुंच मार्ग बनने की उम्मीद है। अफगानिस्तान के संदर्भ में नई दिल्ली के लिए तेहरान भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही पाकिस्तान-समर्थित तालिबान के खिलाफ शासन-साझा करने की व्यवस्था में समान रूप से विरोध कर रहे हैं।

इसके अलावा, ईरान ने पाकिस्तान के लिए भारत के विरोध को समर्थन दिया है, जिसे वह वाशिंगटन का प्रॉक्सी और सऊदी अरब का सहयोगी मानता है। अमेरिका के इशारे पर ईरान से तेल का आयात बंद करने के भारत के फैसले से नई दिल्ली और तेहरान के बीच अलगाव हो सकता है, जिसे फिर से ठीक करना भारत के लिए मुश्किल हो सकता है और यह रणनीतिक रूप से भी भारत को नुकसान पहुंचाएगा।

सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या ईरान तेल आयात को शून्य कर देने की अमेरिकी धमकी के आगे झुक जाएगा और जिन मुद्दों को अमेरिका महत्वपूर्ण मानता है उन मुद्दों को स्वीकार करेगा? इसमें तेहरान के यूरेनियम को समृद्ध करने और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अनुसंधान में लगे लोगों सहित सभी परमाणु सुविधाओं को भी बंद करने का मुद्दा शामिल होगा। इसके अतिरिक्त, यदि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का पूरी तरह उन्मूलन नहीं कर रहा है और सीरिया, इराक, लेबनान तथा यमन में अमेरिकी प्राथमिकताओं के अनुरूप चलने के लिए अपनी पश्चिम एशिया नीति को पूरी तरह से नहीं बदल रहा है, तो यह ईरान को भारी नुकसान पहुंचाएगा।

हालाँकि, यह वाशिंगटन के लिए एक कल्पना के समान ही प्रतीत हो रहा है। ईरान ने चार दशकों तक अभूतपूर्व प्रतिबंधों का सामना किया और अडिग रहा। तेहरान को अपने तेल के निर्यात को शून्य करने के लिए मजबूर करने की वर्तमान अमेरिकी नीति केवल ईरानी कट्टरपंथियों की सहायता करेगी और अंत में तेहरान एक और अधिक शक्तिशाली अमेरिकी विरोधी रवैया अपनाएगा, जिससे इस क्षेत्र में अमेरिकी रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति और बाधित होगी।

एक अंधकारमय परिदृश्य

हालांकि, इस टकराव की नीति इजरायल और सऊदी अरब को खुश कर सकती है, लेकिन यह पश्चिम एशिया में एक और बड़े युद्ध का कारण भी बन सकती है। परमाणु समझौते से हटाये जाने के कारण ईरान द्वारा बदला लिए जाने और हथियार ग्रेड स्तर तक परमाणु संवर्धन को फिर से शुरू किये जाने की संभावना बढ़ गयी है। हालांकि, इसके बाद ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी या इजरायल के हवाई हमलों की भी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अमेरिका द्वारा ईरान पर इस तरह के हमले इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और खाड़ी के आस पास सीधे तौर पर अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी जवाबी कार्यवाई को आमंत्रित करने के लिए बाध्य हैं।

इस क्षेत्र में इस तरह की घटना पश्चिम एशिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है और होर्मुज के संकरे जलडमरूमध्य के माध्यम से ऊर्जा आपूर्ति के प्रवाह को गंभीर रूप से बाधित कर सकती है। यह विडंबना है कि इराक पर अमेरिका के विनाशकारी आक्रमण के कुछ लेखक, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन, ईरान के प्रति मौजूदा अमेरिकी टकराव की नीति के भी मास्टरमाइंड हैं। यदि इसे बदला नहीं गया, तो इस तरह की रणनीति पश्चिम एशिया में एक और अमेरिकी विनाशकारी आक्रमण को जन्म दे सकती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा मिलने की संभावना और बढ़ जाती है।

तेल की बढ़ती कीमतें

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कहा कि अमेरिका ईरानी सरकार पर दबाव बनाने के अभियान को प्रभावशाली ढंग से तेज करेगा और यह तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान के नेता 'विनाशकारी व्यवहार' बदल नहीं लेते हैं, अपने लोगों के अधिकारों का सम्मान नहीं करने लग जाते और बातचीत की मेज पर नहीं बैठ जाते।
- पोम्पिओ की यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा के बाद आई है कि उनका प्रशासन ईरान से तेल आयात करने वाले देशों को अतिरिक्त 'महत्वपूर्ण कटौती अपवाद' जारी नहीं करेगा।

प्रमुख बिंदु

- अमेरिका ने पिछले वर्ष नवंबर में भारत और सात अन्य देशों को 180 दिनों की अवधि के लिये ईरान से तेल आयात में छूट दी थी, जो 2 मई को समाप्त होने वाली है।
- भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और तुर्की इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।
- दुनिया में सऊदी अरब और इराक के बाद ईरान भारत को तेल आपूर्ति करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है।
- ईरान ने अप्रैल, 2017 से जनवरी, 2018 के दौरान भारत को 18.4 मिलियन टन कच्चे तेल की आपूर्ति की है।
- फैसले से भारत समेत आठ देशों को आगामी दो मई तक ईरान से तेल के अपने आयात को नीचे लाना होगा। जबकि, ग्रीस, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान ने पहले ही ईरान से अपने तेल आयात में भारी कमी कर दी है।

प्रतिबंध का प्रभाव

- ईरान के राजस्व का मुख्य स्रोत तेल निर्यात है जो प्रतिबंध की वजह से संकट में आ जाएगा।
- वर्ष 2018 में वैश्विक तेल उत्पादन में ईरान का हिस्सा 4% था। ईरान पर प्रतिबंधों के पश्चात् वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखलाओं पर असर पड़ने की संभावना है।
- आपूर्ति में व्यवधान की वजह से तेल की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
- दुनिया के तीन सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादकों अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि वे वैश्विक तेल बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।
- अमेरिका ने कहा है कि वह तेल प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली किसी भी संस्था या कंपनी पर वित्तीय अंकुश लगाएगा, जिसमें कंपनियों द्वारा स्विफ्ट बैंकिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सिस्टम के उपयोग पर प्रतिबंध, उन कंपनियों की किसी भी अमेरिकी संपत्ति की जब्ती और डॉलर में लेन-देन जैसे प्रतिबंध शामिल हैं।

भारत पर प्रभाव

- **रिफाइनरियों के लिये तेल की आपूर्ति:** अमेरिका के इस निर्णय से भारत पर काफी प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- अमेरिका ने हाल ही में भारत के एक अन्य शीर्ष आपूर्तिकर्त्ता वेनेजुएला पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। इन परिस्थितियों में
- अमेरिका का हालिया निर्णय भारत के लिये मुश्किलें खड़ी कर सकता है।
- आयात बिल में वृद्धि से रुपए पर दबाव पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से महँगाई बढ़ेगी।

ईरान द्वारा प्रदत्त भारत को विशेषाधिकार

- ईरान अन्य देशों को 30 दिन और भारत को 60 दिन की क्रेडिट सीमा देता है।
- ईरान ने भारत को सीधे रुपए में भुगतान करने की भी सुविधा प्रदान की थी। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि कुल राशि का 55% भुगतान यूरोपीय बैंकों में किया जाएगा तथा शेष 45% राशि का भुगतान भारत स्थित बैंक में किया जाएगा जिसका उपयोग भारत से आयात के लिये किया जाएगा।
- इसके बाद, यूरोपीय बैंकों द्वारा भुगतान बंद किये जाने की स्थिति में ईरान ने भारत को 100% भुगतान रुपए में करने की सुविधा दी, यह व्यवस्था ईरान के साथ P 5+1 देशों की संधि होने तक जारी रही।
- पुनः 55% भुगतान यूरो और 45% रुपए में करने की व्यवस्था की गई।
- ईरान भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति के लिये माल ढुलाई में भी छूट प्रदान करता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) 48 देशों का समूह है, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी।
2. भारत, चीन और जापान, ईरान से तेल आयात करने वाले प्रमुख देश हैं।
3. चाहबहार बन्दरगाह दक्षिणी ईरान में फारस की खाड़ी में स्थित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) 2 और 3
(c) 1 और 3
(d) उपर्युक्त सभी

1. Consider the following statements-

1. Nuclear Suppliers Group (NSG) is a group of 48 nations which was established in 1975.
2. India, China and Japan are major oil importing countries of Iran.
3. Chahbahar port is situated in South Iran in Persian Gulf.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) 2 and 3
(c) 1 and 3
(d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः- अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाये गये प्रतिबंध के कारण भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साथ ही इस संबंध में भारत को अपने आर्थिक हित देखते हुए क्या कदम उठाने चाहिए? विवेचना कीजिए।

(250 शब्द)

Q. What effect will be there on the India-America bilateral relations due to the ban on Iran by America, along with it, what steps should India take considering its economic interest? Analyse. (250Words)

नोट : 30 अप्रैल को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।

Committed To Excellence